



ACCELENSE

A Newsletter to Accelerate SDGs

संस्करण 6: सामाजिक लेंस

थीम: सशक्त जन, समावेशी भविष्य



SDG समन्वय और त्वरण केंद्र (स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के तत्वावधान में), हरियाणा आपका स्वागत करता है अपनी पाक्षिक न्यूज़लेटर शृंखला SDG ACCELENSE में — जो ज्ञान साझा करने, विचारों को उजागर करने और सतत विकास को आकार देने वाले नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार की गई है। हमें आशा है कि यह "लेंस" विकासात्मक मुद्दों पर अनेक दृष्टिकोण प्रदान करेगा और जमीनी स्तर पर वास्तविक गति लाएगा, जिससे 'विकसित हरियाणा' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

प्रत्येक संस्करण विकास को तीन में से किसी एक लेंस से देखेगा — सामाजिक लेंस, जो लोगों, समावेश और पर्यावरण की कहानियों को सामने लाता है; टेक लेंस, जो बदलाव के डिजिटल और तकनीकी सक्षमकर्ताओं को रेखांकित करता है; आर्थिक लेंस, जो विकास, वित्त और लचीलेपन पर केंद्रित है।

मिलकर, ये तीनों लेंस राज्य को एक "अविराम जीवन शक्ति" के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे — ताकि हरियाणा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और टिकाऊ बन सके।



Nayab Singh Saini
Hon'ble Chief Minister, Haryana

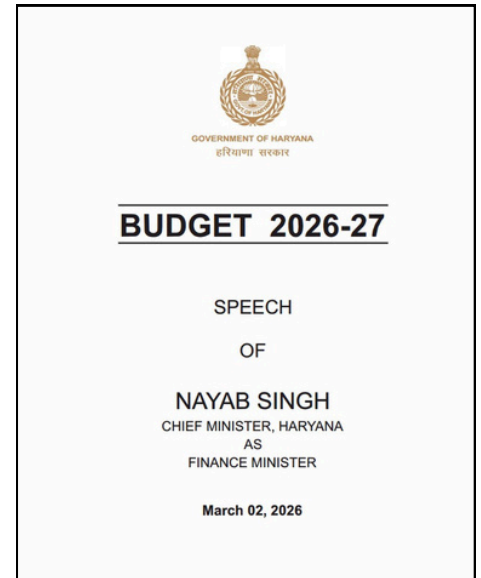
"हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत ने न केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी। लगातार चौथे वर्ष, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक GDP वृद्धि दर दर्ज की है। निस्संदेह, यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम है। हरियाणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 'विकसित भारत' @2047 की दृष्टि की पूर्ति की दिशा में एक अनवरत और अथक विकास के इंजन के रूप में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

[बजट भाषण PDF — आधिकारिक स्रोत](#)

हरियाणा बजट 2026-27 — एक मजबूत, अधिक समावेशी राज्य के लिए ₹2.23 लाख करोड़

2 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा बजट ₹2,23,658.17 करोड़ पेश किया — जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.3% अधिक है। बजट को 'किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, कामगारों और मध्यम वर्ग के उज्ज्वल भविष्य की नींव' बताया गया।

- महिला एवं बाल विकास: ₹2,263.29 करोड़ (↑ 14.91%) — लाडो लक्ष्मी योजना: ₹6,500 करोड़ आवंटित
- सामाजिक न्याय, सेवा एवं अंत्योदय: ₹17,250.72 करोड़ (↑ 15.74%)
- ग्रामीण विकास एवं पंचायत: ₹8,703.74 करोड़ (↑ 22.88%)
- पर्यावरण एवं वन: ₹741.55 करोड़ (↑ 32%) — ग्रीन क्लाइमेट रिसिलिएंस फंड: ₹100 करोड़
- जल सुरक्षित हरियाणा: ₹5,715 करोड़ | हरियाणा AI मिशन: 1 लाख युवाओं के लिए ₹474 करोड़



source:

- <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s386e78499eeb33fb9cac16b7555b50767/uploads/2026/03/202603201031104005.pdf>
- <https://prsindia.org/budgets/states/haryana-budget-analysis-2026-27>



हरियाणा भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना में अग्रणी – CM नायब सिंह सैनी ने स्व-गणना अभियान का शुभारंभ किया



16 अप्रैल 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया — भारत की प्रथम पूर्णतः डिजिटल जनगणना में हरियाणा की सहभागिता। स्व-गणना प्रक्रिया 16-30 अप्रैल 2026 तक संचालित हुई, उसके पश्चात 1-30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना। मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि जनगणना डेटा सीधे विकसित भारत 2047 की दिशा में योजना वितरण को आकार देगा।

- स्व-गणना पोर्टल: se.census.gov.in — बहुभाषी, मोबाइल अनुकूल
- हरियाणा में 7,000 से 65,000 जनगणना कार्यकर्ता प्रशिक्षित
- डेटा गृह मंत्रालय के सुरक्षित सर्वर पर संग्रहीत
- जनगणना का नारा: "हमारी जनगणना, हमारा विकास"
- SDG-संरक्षित नीति नियोजन एवं समावेशी शासन से सीधा संबंध

source:

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2252673®=3&lang=2>

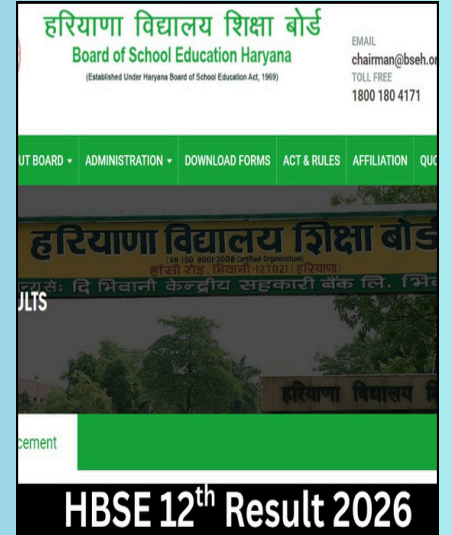
हरियाणा बोर्ड परिणाम 2026 — छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया, कक्षा 12 में 84.67% उत्तीर्ण

BSEH ने 12 मई 2026 को कक्षा 12 के परिणाम घोषित किए — छात्राएँ अग्रणी रहीं। परीक्षा में सम्मिलित 2,42,856 विद्यार्थियों में से 2,05,618 उत्तीर्ण हुए — कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 84.67%। रेवाड़ी की दीपिका ने 499/500 अंकों से राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ग्रामीण विद्यार्थियों का प्रदर्शन शहरी विद्यार्थियों से थोड़ा बेहतर रहा — जो राज्य भर में बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतीक है।

- कुल उत्तीर्ण: 84.67% — छात्राएँ: 87.97%, छात्र: 81.45%
- विज्ञान: 90.08% | वाणिज्य: 88.20% | कला: 82.60%
- राज्य टॉपर: दीपिका (रेवाड़ी) — 499/500 अंक
- राज्यभर के 1,431 परीक्षा केंद्रों पर परिणाम घोषित

source:

- <https://bseh.org.in/recent-news>
- <https://testbook.com/news/hbse-12th-result-2026-out-topper-list/>



हरियाणा ने ग्रीन क्लाइमेट रेसिलिएंस कोष की स्थापना की — नेट-ज़ीरो भविष्य के लिए ₹100 करोड़ की प्रतिबद्धता



हरियाणा बजट 2026-27 में नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ₹100 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ एक समर्पित ग्रीन क्लाइमेट रेसिलिएंस कोष स्थापित किया गया। पर्यावरण एवं वन विभाग को 32% बजट वृद्धि मिली — ₹741.55 करोड़। जल सुरक्षित हरियाणा के लिए ₹5,715 करोड़ तथा 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नया हरियाणा एग्री डिस्कॉम प्रस्तावित।

- ग्रीन क्लाइमेट रेसिलिएंस कोष: ₹100 करोड़ की प्रारंभिक राशि
- पर्यावरण एवं वन बजट: ₹741.55 करोड़ (↑ 32%)
- जल सुरक्षित हरियाणा: संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिए ₹5,715 करोड़
- हरियाणा एग्री DISCOM: 5,084 फीडर, 7.12 लाख उपभोक्ता

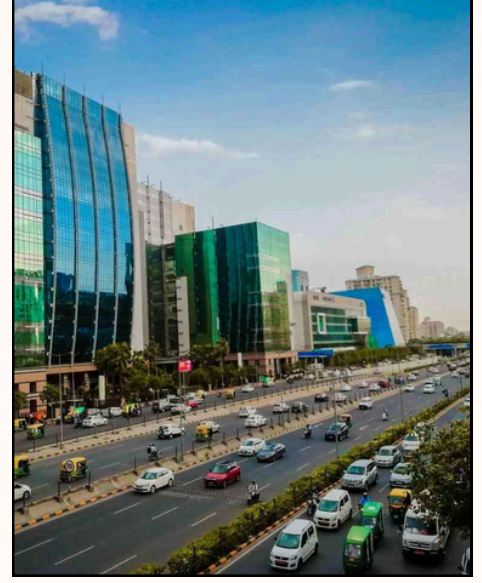
source:

- <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s386e78499eeb33fb9cac16b7555b50767/uploads/2026/03/202603201031104005.pdf>
- <https://prsindia.org/budgets/states/haryana-budget-analysis-2026-27>

हरियाणा – सभी जिलों में आधुनिक एवं समावेशी शहरी विकास

शहरी स्थानीय निकाय एवं नगर नियोजन को बजट 2026-27 में ₹6,797.57 करोड़ आवंटित किए गए — 24.86% की उल्लेखनीय वृद्धि। हरियाणा का शहरी व्यय राष्ट्रीय राज्य औसत से अधिक है (3.8% बनाम 3.2%)। अंत्योदय सरल पोर्टल 600 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है तथा SAKSHAM कोष (₹500 करोड़) पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु समर्पित है।

- शहरी स्थानीय निकाय एवं नगर नियोजन: ₹6,963 करोड़ (↑ 25%)
- हरियाणा का शहरी व्यय: 3.8% बनाम 3.2% राष्ट्रीय राज्य औसत
- अंत्योदय सरल पोर्टल: 600+ ऑनलाइन सरकारी सेवाएं
- SAKSHAM कोष: पुराने औद्योगिक क्षेत्र पुनरुद्धार के लिए ₹500 करोड़



source:

- <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s386e78499eeb33fb9cac16b7555b50767/uploads/2026/03/202603201031104005.pdf>
- <https://prsindia.org/budgets/states/haryana-budget-analysis-2026-27>

NITI आयोग ने विद्यालय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 13-सूत्रीय रोडमैप जारी किया

भारत विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय शिक्षा प्रणाली संचालित करता है — 14.71 लाख विद्यालय, 24.69 करोड़ छात्र, 1.01 करोड़ शिक्षक। NITI आयोग के 13-सूत्रीय रोडमैप में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSAs), दक्षता-आधारित पाठ्यक्रम और AI-सक्षम वैयक्तिक शिक्षण का प्रस्ताव है। 94.5% निजी विद्यालयों में अब इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

- 14.71 लाख विद्यालय | 24.69 करोड़ छात्र | 1.01 करोड़ शिक्षक
- 94.5% निजी विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा
- 13-सूत्रीय योजना: AI शिक्षा, SSSAs, दक्षता-आधारित पाठ्यक्रम

source:

- <https://niti.gov.in/sites/default/files/2026-05/School-Education-System-in-India.pdf>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2258645®=3&lang=1>

NITI आयोग ने SDG 5 जिला रिपोर्ट लॉन्च की — प्रत्येक जिले के लिए लैंगिक समानता आँकड़े

NITI आयोग ने IIM अहमदाबाद, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा गुजरात सरकार के सहयोग से 792 जिलों में 26 संकेतकों पर SDG 5: लैंगिक समानता की राज्य, संघ राज्यक्षेत्र एवं जिला रिपोर्ट लॉन्च की — भारत का सबसे विस्तृत लैंगिक डेटा संकलन अभ्यास। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी: "उच्च गुणवत्ता वाला डेटा, तकनीक-सक्षम निगरानी के साथ सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र गतिशील नीति निर्माण के लिए अनिवार्य है।"

- 792 जिलों में 26 लैंगिक समानता संकेतकों का अनुसरण
- मुख्य विषय: कौशल विकास, वित्तीय समावेश, लैंगिक-उत्तरदायी बजटिंग, देखभाल अर्थव्यवस्था
- UNDP, UNICEF, UN Women, विश्व बैंक ने कार्यशाला में सहभागिता की

source:

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2259092®=3&lang=1>



UNESCO: 78 देशों के विद्यालय पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन अनुपस्थित — भारत को नेतृत्व करना चाहिए

UNESCO की GEM रिपोर्ट 2026 एक महत्वपूर्ण SDG 4 अंतराल उजागर करती है: 78 देशों में कक्षा 3, 50 देशों में कक्षा 6 और 28 देशों में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन का समावेश नहीं है। भारत के लिए, जहाँ NEP 2020 समग्र शिक्षा पर बल देती है, यह भविष्य के जलवायु-साक्षर नागरिकों के निर्माण का अवसर है।

source:

- <https://www.unesco.org/reports/gem-report/en/2026-monitoring-sdg4>
- <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392406>



MONITORING REPORT

भारत BRICS MSME एजेंडे का नेतृत्व करता है — लघु उद्यमों के लिए वित्तीय समावेश केंद्र में

2026 में BRICS की अध्यक्षता करते हुए भारत ने PartNIR के अंतर्गत MSME सहयोग का नेतृत्व किया। प्रथम BRICS SME कार्यसमूह बैठक (24 अप्रैल 2026) 'MSME के लिए वित्त तक पहुँच' पर केंद्रित रही। भारत ने जापान, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ MSME सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- 7.47 करोड़ MSME उद्यमों में 32.82 करोड़ लोगों को रोज़गार | भारत की GDP में 31.1%
- देश के कुल निर्यात में 48.58% की हिस्सेदारी
- 2026 में उद्घाटन BRICS MSME फोरम के आयोजन की योजना

source:

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2258985®=3&lang=1>



UN Women रिपोर्ट — महिला पत्रकारों के विरुद्ध ऑनलाइन हिंसा एक निर्णायक स्थिति में

30 अप्रैल 2026 को UN Women द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पुष्टि करती है कि महिला पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों के विरुद्ध ऑनलाइन हिंसा एक गंभीर स्तर पर पहुँच गई है — और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) इसे और विकट बना रही है। रिपोर्ट 'Tipping Point: Online Violence — Impacts, Manifestations and Redress in the AI Age' 119 देशों में 641 महिलाओं के वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है।

- सर्वेक्षण में 70% महिलाओं ने कार्यक्षेत्र में ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया
- पुलिस को रिपोर्ट 2020 से दोगुनी — महिला पत्रकारों में 11% से 22%
- 45% महिला पत्रकार सोशल मीडिया पर स्व-सेंसरशिप करती हैं — 2020 से 50% वृद्धि
- 4 में से 1 महिला पत्रकार में ऑनलाइन दुर्व्यवहार से जुड़ी मानसिक चिंता/अवसाद
- डीपफेक एवं छवि हेरफेर सहित AI उपकरण दुर्व्यवहार के नए रूप उत्पन्न कर रहे हैं

source:

- <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2026/04/reports-to-police-of-online-violence-against-women-journalists-double-since-2020-with-one-in-four-experiencing-related-anxiety-and-or-depression>
- <https://news.un.org/en/story/2026/04/1167416>



NEARLY HALF OF WOMEN JOURNALISTS

report self-censorship on social media due to online violence.

वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 – भारत की वन आवरण वृद्धि हरियाणा के लिए मार्गदर्शक

UN वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 संयुक्त राष्ट्र वन रणनीतिक योजना 2017–2030 के अंतर्गत 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 उद्देश्यों की प्रगति का आकलन करती है। भारत ने 1,445 वर्ग किमी वन आवरण जोड़ा, जिससे वह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 वन-वृद्धि प्राप्त देशों में सम्मिलित है — हरियाणा के अरावली हरित पट्टी विस्तार के लिए यह एक प्रासंगिक मॉडल है।

source:

- <https://www.un.org/en/climatechange/reports>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2086742®=3&lang=2>



कार्यक्रम विशेष

हरियाणा कार्बन कनेक्ट – UNDP-SDGCAC ज्ञान शृंखला वेबिनार

UNDP-SDGCAC ज्ञान शृंखला के अंतर्गत, सतत विकास लक्ष्य समन्वय और त्वरण केंद्र (SDGCAC), हरियाणा ने 8 अप्रैल 2026 को "हरियाणा कार्बन कनेक्ट: कार्बन दायित्वों को आर्थिक संपदा में बदलना" शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन किया।

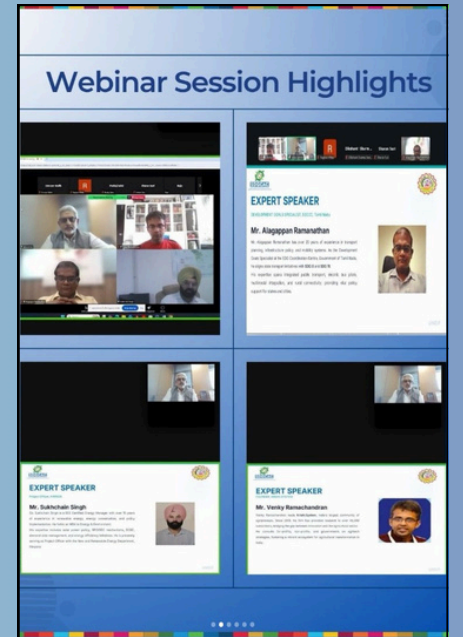
इस वेबिनार में परिवहन, ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों के विशिष्ट विशेषज्ञों ने हरियाणा के सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में कार्बन बाजारों की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार-विमर्श किया।

प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे —

श्री अलगप्पन रामनाथन, विकास लक्ष्य विशेषज्ञ, SDGCC तमिलनाडु, जिन्होंने सतत गतिशीलता और कार्बन बाजार ढाँचों पर अपने विचार साझा किए; श्री सुखचैन सिंह, परियोजना अधिकारी, HAREDA, जिन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में हरियाणा की संभावनाओं को रेखांकित किया; श्री वेंकी रामचंद्रन, संस्थापक, Krishi.System, जिन्होंने पुनर्योजी कृषि और कृषि कार्बन बाजारों में किसान-केंद्रित दृष्टिकोणों पर चर्चा की।

सत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, निम्न-कार्बन भवन निर्माण, जलवायु-स्मार्ट कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन में अवसरों की पड़ताल की गई। साथ ही, सशक्त संस्थागत समन्वय, नीतिगत अभिसरण और नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

इस वेबिनार ने उप-राष्ट्रीय कार्बन बाजार विकास में अग्रणी राज्य के रूप में हरियाणा की क्षमता को पुनः रेखांकित किया और यह दर्शाया कि किस प्रकार कार्बन क्रेडिट — सतत आर्थिक विकास, जलवायु लचीलेपन और SDG-संरेखित विकास मार्गों को समर्थन दे सकते हैं।





सतत विकास लक्ष्य समन्वय और त्वरण केंद्र (स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान)

हमसे जुड़ें:

